गांवों में रफ्तार पकड़ता 'डिजिटल इंडिया'

—बालेन्दु शर्मा दाधीच

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल तकनीक के माध्यम से आम लोगों का जीवन आसान बनाना है बल्कि गांवों को डिजिटली साक्षर कर 'वैश्विक गांव' में तब्दील करना है। इसी के मद्देनजर बजट 2016-17 में आने वाले तीन वर्षों में छह करोड़ घरों के ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल दुनिया से जोड़ देने का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं डिजिटल साक्षरता के काम को स्किल डेवलपमेंट योजना में शामिल कर लिया गया है। इससे रोजगार की भी अपार संभावनाएं पैदा होंगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 'डिजिटल इंडिया' के बारे में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए बिंदुवार ढंग से बताया कि उनकी नजर में 'डिजिटल इंडिया' के मायने क्या हैं और जब वे 'डिजिटल इंडिया' की बात करते हैं तो कौन से भारत का सपना देखते हैं। 'डिजिटल इंडिया' पहल प्रधानमंत्री की अपनी भविष्योन्मुखी दृष्टि पर आधारित है और भारत की विकास प्रक्रिया में योगदान देने वाली है इसलिए उनका यह बयान बेहद अहम हो जाता है जो उन्होंने हाल ही में इंडिया डिजिटल समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए दिया। पिछले एक साल से 'डिजिटल इंडिया' के संदर्भ में चल रही गतिविधियों और घटनाक्रम को प्रधानमंत्री का यह संबोधन एक स्पष्ट दिशा और दृष्टि देता है।

श्री मोदी ने एक–एक कर अपने विज़न को स्पष्ट करते हुए कहा कि वे एक ऐसे डिजिटल भारत का सपना देखते हैं–

- जहां 1.20 अरब कनेक्टेड भारतीय नवाचार (इनोवेशन) को बढ़ावा देने में जुटे हों।
- जहां ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति के रूप में लोगों को सक्षमता प्रदान करे।
- जहां सूचनाओं तक पहुंच के मार्ग में कोई बाधा न हो।

- जहां सरकार खुली और पारदर्शी हो।
- जहां टेक्नोलॉजी यह सुनिश्चित करे कि सरकार और नागरिकों के बीच संपर्क के माध्यम भ्रष्ट नहीं किए जा सकें।
- जहां सरकारी सेवाएं मोबाइल उपकरणों के माध्यम से नागरिकों को सुगमता से उपलब्ध हो सकें।
- जहां सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ खुलकर संवाद करे।
- जहां डिजिटल शिक्षा के माध्यम से समाज के दूरदराज के क्षेत्रों तक भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बने।
- जहां तेज रफ्तार डिजिटल हाईवे देश को जोड़ते हो।
- जहां ई–हेल्थ केयर के माध्यम से प्रदत्त गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सर्वाधिक दूरस्थ क्षेत्रों तक भी उपलब्ध हों।
- तत्क्षण सूचनाएं किसानों को वैश्विक बाजारों से जुड़ने में समर्थ बनाएं।
- मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध आपातकालीन सेवाएं निजी सुरक्षा सुनिश्चित करें।
- साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग हो।
- मोबाइल बैंकिंग वित्तीय समावेश सुनिश्चित करे।
- ई–कॉमर्स उद्यमिता को प्रोत्साहित करें।
- दुनिया अगले बड़े विचार के लिए भारत की ओर देखे।
- इंटरनेट से जुड़ा हुआ नागरिक एक सबल नागरिक हो।

डिजिटल इंडिया के प्रति प्रधानमंत्री की समग्र परिकल्पना का उल्लेख करना इस मायने में भी जरूरी है चूंकि श्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि में हमारे गांव इस भविष्योन्मुखी अवधारणा का एक प्रमुख अंग हैं। भले ही वह सवा अरब नागरिकों को इंटरनेट से जोड़ने की आकांक्षा हो, भले ही सरकारी सेवाओं को मोबाइल उपकरणों के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाने का सपना हो, भले ही डिजिटल शिक्षा को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने का संकल्प हो, भले ही देश के सर्वाधिक दूरस्थ क्षेत्रों तक ई–हेल्थ केयर के जरिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य हो और भले ही इंटरनेट से जुड़े हर नागरिक को एक सबल–सक्षम–समर्थ नागरिक में बदल देने का इरादा हो, यह सिद्ध करता है कि डिजिटल इंडिया की अवधारणा एक समावेशी अवधारणा है और ग्रामीण भारत उसमें बड़ी अहमियत रखता है।

डिजिटल इंडिया से गांवों में बदलाव की बात कोई सपना या कागजी योजना नहीं है। हालांकि कार्य चुनौतीपूर्ण है और देश में पर्याप्त बिजली की सप्लाई तथा आधारभूत सुविधाओं का अभाव एक बड़ी रुकावट है किंतु ये रुकावटें भारत की एक सच्चाई हैं। डिजिटल इंडिया जैसी पहल आज की जाती है तब भी और यदि यह 10 साल बाद की जाती है तब भी, ऐसी चुनौतियां हमारे सामने इसी तरह खड़ी होने वाली हैं। इन हालात में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए समाधान के वैकल्पिक मार्ग निकालना एक अनिवार्यता है। सरकार को इन चुनौतियों का अहसास है और वह उनसे निपटने के रास्तों की तलाश भी कर रही है। यह नजरिया बहुत अधिक अहमियत रखता है।

मिसाल के तौर पर वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (वीएनओ) की अवधारणा को देखिए। दूरसंचार क्षेत्र में एक ओर जहां रिलायंस जिओ टेलीकॉम जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने में जुटी हैं और सरकार की ओर से राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार दूरसंचार तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नई सोच से भी काम ले रही है। वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर ऐसी कंपनियां होंगी जिनके पास अपना स्पेक्ट्रम नहीं है लेकिन जिन्हें किसी खास क्षेत्र में दूरसंचार सुविधाएं मुहैया कराने का अधिकार होगा। ये लाइसेंसशुदा दूरसंचार कंपनियां नहीं हैं लेकिन ये लाइसेंसशुदा ऑपरेटरों से एयरटाइम खरीदेंगी और उसे उपभोक्ताओं को बेचेंगी। जिन दूरसंचार ऑपरेटरों के पास किसी खास क्षेत्र में अच्छा नेटवर्क नहीं है या आधारभूत सुविधाओं की कमी है वह एक तीसरे पक्ष को एयर टाइम बेच सकेगा जो उस क्षेत्र में बेहतर पैठ रखता है। इससे अलग स्तर पर आधारभूत सुविधाओं का विकास होने लगेगा। दूरसंचार के साथ–साथ इसी तरह का विकल्प इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी उपलब्ध होगा।

केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने अगले दो–तीन वर्षों के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मिसाल के तौर पर यह कि सन 2018 तक भारत में 50 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे। उसी वर्ष बाजार में आने वाले हर मोबाइल फोन में ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली ई–सुविधा मौजूद होगी। एक और घोषणा यह है कि भारत संचार नेटवर्क लिमिटेड (बीएसएनएल) सन 2018 में एक बार फिर से लाभप्रद कंपनी बन जाएगी। तब तक बीएसएनएल भारत में 40,000 वाइ–फाइ हॉटस्पॉट स्थापित कर दिए जाएंगे। ये सब घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आने वाले वर्षों में डिजिटलीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। आपको याद होगा डिजिटल इंडिया की शुरुआत के समय विभिन्न कंपनियों ने लगभग 4.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी।

दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की घोषणाएं इसलिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज भी भारत की वयस्क आबादी के सिर्फ 22 प्रतिशत हिस्से को इंटरनेट तक पहुंच हासिल है जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 67 प्रतिशत है। न्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण के अनुसार जहां भारत के शहरी क्षेत्रों में हर 1000 घरों में से 487 के पास इंटरनेट तक पहुंच उपलब्ध है वही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 घरों में से सिर्फ 161 के पास यह विकल्प मौजूद है।

डिजिटल इंडिया के सफल क्रियान्वयन के संदर्भ में श्री प्रसाद द्वारा परिकल्पित 5 स्तंभों की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ये पांच स्तंभ हैं– कोर बैंकिंग सुविधाओं से युक्त सवा लाख डाकघर, देश के कोने–कोने में फैला ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, 1.57 लाख सामान्य सेवा केंद्र, बड़े पैमाने पर खोले जाने वाले ग्रामीण बीपीओ या कॉल सेंटर और और वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर। यह सब मिलकर इंटरनेट और दूरसंचार तकनीकों पर आधारित सेवाओं की डिलीवरी का टिकाऊ तंत्र स्थापित करेंगे जिसे 'आधार' के साथ जोड़ा जाएगा।

श्री प्रसाद को उम्मीद है कि इस विशाल तंत्र का लाभ न सिर्फ ई–कॉमर्स कंपनियों, ब्रॉडबैंड कंपनियों आदि द्वारा अपनी सेवाओं को दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में किया जाएगा बल्कि बड़े पैमाने पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में भी किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सरकारी सेवाओं को गांव–गांव तक पहुंचाने में भी इन पांच स्तंभों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

इसी तरह की नई सोच के बीच डिजिटल इंडिया अभियान रफ्तार पकड़ने लगा है। इस संदर्भ में हाल ही में शुरू हुई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर एक नजर डालना प्रासंगिक होगा। राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल (विशाल वेबसाइट) के तहत हाल ही में निशक्त लोगों के लिए अलग से एक रोजगार पोर्टल की शुरुआत हुई है। इसके माध्यम से निशक्त लोग शैक्षणिक ऋण और कौशल प्रशिक्षण के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से महिला ई–हाट नामक ऑनलाइन प्लेटफार्म की शुरुआत की गई है। यहां ग्रामीण महिलाएं सीधे अपने उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए जाने वाले भुगतानों के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) की शुरुआत की गई है। यह वर्चुअल माध्यमों से किए जाने वाले भुगतानों को किसानों को अधिक सुरक्षित, सटीक और तीव्र बनाने में योगदान देगी।

महाराष्ट्र के 6 जिलों में ग्रामीण भूमि नक्शा नवीसी और इन नक्शों के डिजिटलीकरण का काम शुरू हुआ है। तेलंगाना राज्य ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की है। कोच्चि के नौसैनिक केंद्र में देश की पहली ई–पेंशन अदालत लगाई गई है। यहां पेंशन से संबंधित मामलों का तुरंत निपटारा करने के लिए पेंशन विभाग और बैंक अधिकारी उपस्थित थे। उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मौके पर ही कई विवाद निपटाए, जिनका पुराने तौर–तरीकों से महीनों में समाधान हो पाता।

दूरदर्शन की ओर से भी एक सेवा की शुरुआत हुई है जिसके तहत बिना इंटरनेट मोबाइल फोन पर टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ है। फिलहाल ये प्रसारण 4 महानगरों तथा 12 अन्य बड़े शहरों में शुरू हुए हैं। भारतीय रेलवे ने पिछले दिनों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत अपने टिकट कलेक्टरों के लिए हाथ में रखी जाने वाली टर्मिनल मशीनें लांच की हैं। रेल टिकट कटवाने के लिए कागज रहित मोबाइल एप्लीकेशन की भी शुरुआत हुई है। 408 रेलवे स्टेशनों पर ई–केटरिंग की सेवा शुरू की गई है जिसके तहत यात्री मोबाइल फोन के माध्यम से अपनी पसंद के भोजन का आदेश दे सकेंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने ई–हेल्थ पहल के तहत अनेक नई सुविधाओं की शुरुआत की है जिनमें इ–रक्त कोष नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी शामिल है जो किसी भी क्षेत्र में किसी खास रक्त समूह चेहरे की उपलब्ध मात्रा का ब्यौरा देता है। आयकर विभाग ने ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए नए तकनीकी टूल का प्रयोग शुरू किया है जिनके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं। तात्पर्य यह है कि डिजिटल इंडिया के तहत अलग–अलग क्षेत्रों में, अलग–अलग विभागों द्वारा,

अलग–अलग उद्देश्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए आधुनिक सुविधाओं का विकास तेजी पकड़ रहा है।

केंद्र ही क्यों, राज्यों के सरकारी मंत्रालयों, विभागों, जिला मुख्यालयों और गांवों से भी ऐसी खबरें आने लगी हैं जिनसे एक सकारात्मक माहौल बनता हुआ प्रतीत होता है। अब यह बात बार–बार सिद्ध करने की जरूरत नहीं रही कि सूचना प्रौद्योगिकी विशेषकर इंटरनेट और मोबाइल युक्तियों के इस्तेमाल से तमाम तरह की सेवाओं को अधिक सुगम, तेज रफ्तार, व्यापक और प्रभावी बनाना संभव है। यह संदेश भी प्रशासन और कारोबार के विभिन्न स्तरों तक पहुंच गया लगता है कि आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में तकनीक का प्रयोग अब अवश्यंभावी है। विकास को बढ़ावा देने के साथ–साथ यह अनेक पारंपरिक चुनौतियों और रुकावटों को दूर करने में भी मदद करेगा, जैसे कि भ्रष्टाचार।

पिछली एक मई को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के संपूर्ण डिजिटलीकरण का सिलसिला शुरू हो गया जब जिले के 5 गांवों को औपचारिक रूप से 'डिजिटल ग्राम' घोषित किया गया। इस साल अगस्त तक नागपुर जिले की 776 ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पहुंच जाएगा और इस तरह नागपुर जिला देश का पहला पूर्ण डिजिटल जिला बन जाएगा। राज्य सरकारों ने डिजिटल इंडिया से प्रेरित होकर अपने–अपने स्तर पर भी डिजिटलीकरण की योजनाएं शुरू की हैं। महाराष्ट्र सरकार की डिजिटल ग्राम योजना के तहत राज्य के अनेक गांव डिजिटलीकृत किए जाने हैं।

तेलंगाना राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ा है। निजामाबाद जिले के नरसिंहपुर गांव को सौ फीसदी डिजिटल साक्षर बनाने का अभियान शुरू हुआ है। इससे पहले बसरा गांव राज्य का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर गांव बन चुका है। इस परियोजना में तेलंगाना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन और तेलंगाना विश्वविद्यालय मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसी परियोजनाएं और ऐसा माहौल सरकारी और निजी भागीदारी का स्वतः स्फूर्त सिलसिला शुरू होने की उम्मीद बंधाता है।

जैसाकि हमने ऊपर जिक्र किया यदि देश के राज्य और जिलों ने डिजिटल इंडिया की भावना को अंगीकार कर लिया तो देश में विभिन्न स्तरों और विभिन्न रूपों में डिजिटलीकरण की शृंखला शुरू हो जाएगी। तब वह हमारे आर्थिक–सामाजिक और तकनीकी पर्यावरण का हिस्सा बन जाएगी और डिजिटल इंडिया अभियान पर ही पूरी तरह निर्भर नहीं रह जाएगी। इस तरह की डिजिटल संस्कृति और सोच सारी प्रक्रिया को दीर्घकालीन रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए जरूरी है। विकासमान भारत के लिए वह एक आदर्श स्थिति होगी जब जिले–जिले से डिजिटलीकरण के अभियान शुरू होते हुए दिखाई देंगे।

हाल ही में खबर आई थी कि डिजिटल इंडिया के तहत किए गए अपने वायदे के अनुसार अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने टेलीविजन व्हाइट स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उठाया था। कंपनी ने कुछ गांवों में प्रायोगिक तौर पर इस तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके दिखा दिया है। गूगल ने 10 रेलवे स्टेशनों पर वाइ–फाइ इंटरनेट ब्रॉडबैंड सुविधा देना शुरू किया है। अगले कुछ वर्षों में यह कंपनियां प्रधानमंत्री की आकांक्षा के अनुरूप ही देश के कोने–कोने में इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया करा देंगी।

केंद्र सरकार के स्तर पर डिजिटल इंडिया के तहत आने वाली परियोजनाओं को लालफीताशाही से बचाने, मंजूरी तथा क्रियान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं को आसान व त्वरित बनाने और उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनाने की चेष्टा भी दिखाई देती है। आखिरकार यह ऐसी पहल है जिसकी कामयाबी सिर्फ केंद्र सरकार के प्रयासों पर निर्भर नहीं करती। इसकी कामयाबी का दारोमदार सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ–साथ उपभोक्ता के स्तर पर होने वाली भागीदारी पर भी रहेगा। पिछले एक साल में हुआ काम उम्मीद बंधाता है।

(लेखक वरिष्ठ तकनीकविद् और स्तंभकार हैं।)
ई–मेलः balendudadhich@gmail.com